© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 2 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

बिहार में उच्च शिक्षा : दशा और दिशा

डॉ. श्रवण कुमार
पूर्व शोध छात्र,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा, भारत।

शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के लिए विकास की धूरी है और यह किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। किसी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, यदि शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट एवं वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरुप है तो निश्चित रुप से विकास की संभावनायें प्रबल होगी। जिस देश या समाज में साक्षरता जितनी अधिक होगी, वहाँ की जनता उतनी ही जागरुक और प्रगति पथ पर होगी। देश में शिक्षा का स्वरुप और शैक्षणिक व्यवस्था इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करती है कि शिक्षण संस्थानों की स्थिति कैसी है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा की स्थिति अपेक्षानुसार नहीं रही है तथा उच्च शिक्षा की स्थिति को बेहतर दिशा देने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं।

शिक्षा का तात्पर्य सीखने, जानने, विद्या ज्ञान से है। उच्च शिक्षा शब्द से स्पष्ट है-उँचा, श्रेष्ठ व उत्कृष्ट ज्ञान, उच्च-स्तरीय विद्या, जानकारी, अज्ञात तथ्यों, सत्यों व रहस्यों पर से परदा का उठना, अनुसंधान, प्रत्यक्षीकरण जिसका उपयोग कर जीवन के स्तर को उँचा एवं उत्कृष्ट बनाया जा सके, भौतिक एवं आध्यात्मिक, वाह्य एवं आंतरिक समस्याओं का समाधान किया जा सके, कष्टों से निजात पाया जा सके। ऋषि वाक्य है- "सा विद्या या विमुक्तये।'' महात्मा गाँधी ने कहा था- "मैं उच्च शिक्षा उसी को कहूँगा जिसे पाकर मनुष्य विनम्र, परोपकारी, सेवाभावी और कर्म तत्पर हो जाए। जिस विद्या से आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, वही वास्तविक विद्या है।''

शिक्षा वह पूर्ण अवस्था है जहाँ व्यक्ति की संभावनाओं, प्रभावों और प्रतिभाओं की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, किन्तु आज ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम अपने आदर्शों और सिद्धांतों से विलग हो गये हैं। आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से निकलने वाला अधिकांश व्यक्ति स्वकेन्द्रित और अभिमानी हो रहा है, जबकि उसे संवेदनशील, शांत, पवित्र और विश्वबधुत्व की भावना से ओत-प्रोत महामानव होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय परिवेश में शैक्षिक सुधार की प्रासंगिकता काफी बढ़ गयी है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में जो प्राचीन काल से ही उच्च शिक्षा का प्रमुख अध्ययन केन्द्र रहा है, यहाँ अध्ययन करने के लिए विदेशों से छात्र आते थे, परन्तु वर्तमान समय में बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है।

बिहार में उच्च शिक्षा की बदहाल स्थिति कोई छुपी हुई बात नहीं है, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, उच्च शिक्षा को लेकर गंभीरता और संवेदनशीलता शायद ही कभी देखने को मिली है। बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एकाध अपवादों को छोड़ दें तो शेष सभी शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की भारी कमी से जुझ रहे हैं। जो थोड़े बहुत शिक्षक हैं, उनमें से भी ज्यादातर का पढ़ाई-लिखाई से दूर का रिष्ता है। यह संयोग नहीं है कि बिहार के सबसे प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय में जब नैक की टीम दौरा करने

पहुँची और उसने विभिन्न विभागों के शिक्षकों से उनकी अकादमिक उपलब्धि के बारे में जानना चाहा तो रिसर्च प्रोजेक्ट, देश-विदेश में आमंत्रित व्याख्यान और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की तो बात छोड़ दें, अधिकांश के पास दो-चार आर्टिकिल्स और कुछेक सेमिनार सर्टिफिकेट के अलावे कुछ भी दिखाने को नहीं था। सूबे के अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति तो और भी गयी-गुजरी है। यह वाकई बेहद शर्मनाक स्थिति है कि बिहार के मुख्यमंत्री अपने सौ साल पुराने विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए याचक के तौर पर खड़े रहते हैं, जबकि उन्हें अपनी इस धरोहर को न सिर्फ सहेजना चाहिए बल्कि पुरानी प्रतिष्ठा कैसे वापस आये इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस देश में कई सारे बेहतरीन राज्य विश्वविद्यालय हैं, आप एक विश्वविद्यालय की स्थिति नहीं सुधार सकते तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की तो उम्मीद ही बेमानी है। बिहार में आज राज्य के छात्र खुद को बाहरी प्रदेश के छात्रों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं पाते तो इसके लिए बिहार शिक्षा व्यवस्था और इसके कर्ता-धर्ता कसूरवार हैं। स्पेशल लेक्चर, सिम्पोजियम, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स, रिसर्च प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स यह सब उच्च शिक्षा का हिस्सा है। बिहार में इनमें से कितना कुछ होता है, आप खुद से पूछकर देखिये। अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले शोध पत्रों में बिहार के शिक्षकों और छात्रों के शोध पत्रों का प्रतिशत नगण्य है। अन्तर-अनुशासिक अध्ययन करने वाले के लिए यहाँ की उच्च शिक्षा में आज कोई जगह तक नहीं है। आई.सी.एस.एस.आर. समेत तमाम फंडिंग एजेन्सियाँ विदेषों में सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स में भाग लेने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ पीएच.डी. स्कॉलर्स तक को पैसा देती है, बिहार में गिनती करके बताईये, कितने प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर्स ने इस सुविधा का इस्तेमाल किया है। सुनने में भले ही यह बात अटपटी लगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि जिन मानकों को पूरा कर बिहार में लोग प्रोफेसर पद को सुशोभित कर रहे हैं उन योग्यताओं के सहारे देश में कई विश्वविद्यालयों में आप असिसटेन्ट प्रोफेसर नहीं बन सकते। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त कुव्यवस्था और शिक्षकों के नकारेपन को छुपाने के लिए मानक ही बदल दिये गये हैं। एक वक्त था जब नालन्दा, विक्रमशीला जैसे विख्यात शिक्षा केन्द्र भारतवर्ष का गौरव हुआ करते थे। यहाँ के ज्ञान से पूरा विश्व आलोकित हुआ। बीच के कालखण्ड में भी इस क्षेत्र के शिक्षा केन्द्रों ने अपनी प्राचीन परम्परा को बनाये रखा। लेकिन भारत की आजादी के बाद बिहार में शिक्षा के ऐसे बुरे दिन शुरु हुए कि साल दर साल हमारी यह महान गौरवशाली परम्परा सियासत की भेट चढ़ती चली गयी। वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल छिपा नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा सब की दशा एक जैसी ही है, सब गर्त में है। शिक्षा व्यवस्था के बुरे हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी के जमाने में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए एम.बी.ए. और पीएच.डी. धारक बड़ी संख्या में अप्लाई कर रहे हैं।

अगर बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था में कुछ गुणात्मक बदलाव की पहल सरकार को करनी है तो उसको बाजारपरक गरीब विरोध नीतियों को छोड़कर नये सिरे से विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा। शिक्षा में फंडिग को बढ़ाना होगा, शिक्षकों और कर्मचारियों को भारी संख्या में स्थायी करना होगा, संसाधनों का विस्तार करना होगा। शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न अवयवों को भी एकजुट होकर सरकार पर भारी दवाब बनाने की जरुरत है। यू.जी.सी. को प्राचार्यों को बुलाकर ऑटोनॉमी पर वर्कशॉप करने की जगह शिक्षा के बिगड़ते हालात को कैसे दुरुस्त करें, इस पर वर्कशॉप और परिचर्चा आयोजित करनी चाहिए।

शिक्षा नीति इस प्रकार की हो जो योग्यता का सम्मान करे तथा अनेक प्रकार के बंधन जो कि शिक्षा और अनुसंधान के मार्ग में बाधक है उनको शिथिल करे या बिल्कुल समाप्त करने की दिशा में ठोस पहल करे। आज भारत स्वतंत्र है हमें किसी भी क्षेत्र में बिचैलियों की आवश्यकता नहीं है जैसे कि अंग्रेजी कालखण्ड में थी। अत: हमें स्थानीय दृष्टिकोण से मातृ भाषा में अध्ययन/अध्यापन एवं

अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के महत्व को समझते हुए उसकी भी व्यवस्था एक निश्चित आयु तथा कक्षा के बाद करने की व्यवस्था हो। भारत की शिक्षा को लेकर अभी तक जो भी आयोग बने हैं उनकी अनुशंसाओं को व्यावहारिक रुप प्रदान करने के लिए सार्थक पहल करने की महती आवश्यकता है।

बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था लम्बे समय तक विश्व के अनेक देषों का मार्गदर्शन करती रही है। फिर ऐसा क्या हुआ वह आज मार्गदर्शन नहीं कर सकती? आवश्यकता है इस दृष्टिकोण से सोचने की और उस सोच के आधार पर संरचना खड़ा करने की, जिसमें शिक्षा के दृष्टिकोण से समाज की भूमिका सुनिश्चित हो। यही समय है इस ओर सोचने का और कदम उठाने का। पश्चिमी देशों ने वही किया जो उनके देश, काल और परिस्थिति के लिए उपयोगी था। अतीत में हमने भी ऐसा ही किया था, किन्तु आज हम व्यामोह में फंसकर समुचित कर्मों को उठाना भूल कर पश्चिम का अनुसरण करने लगे हैं। अगर देश के विकास के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तीन घंटे की परीक्षा प्रणाली से किताबी ज्ञान का बेहतरीन परिचय देने वाले युवाओं के साथ हमें उद्यमी, वैज्ञानिक, आविष्कारक और स्वावलम्बन के आधार पर रोजगार उत्पन्न करने वाली युवा शक्ति की आवश्यकता है।

आज शिक्षण संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता देकर समाज उन्मुखी कार्य करने को प्रोत्साहित करने की आवष्यकता है। भारत में जिन संस्थानों को हमने पूर्व में यह स्तर प्रदान किया है, उन संस्थानों ने विश्व में अपना स्थान बनाया है। इसलिए समस्त बंधनों से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में आए जो अतीत पर गर्व करना सिखाए और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इसके लिए बिहार की उच्च शिक्षा को शिक्षा की मूलभूत संकल्पना के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप जब तक पाठ्यक्रम में मूलभूत बुनियादी बदलाव और परिवर्तन नहीं किये जायेंगे तब तक तो यह तस्वीर बदलने वाली नहीं है। आज हमें ऐसे पाठ्यक्रम की जरुरत जो छात्रों में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक संवेदनशीलता तथा समानता को विकसित करे। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरुरत है, जो युवाओं में नागरिक जिम्मेदारी, राष्ट्र प्रेम, आलोचनात्मक चिन्तन और निर्णय क्षमताओं को प्रोत्साहित करे तथा परिस्थिति के अनुसार समस्याओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करे। व्यावहारिक ज्ञान और नैतिकता के साथ बुनियादी प्रशिक्षण भी आवष्यक है, जो कि विद्यार्थियों में जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न कर सके। साथ ही प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और ई-शिक्षा के अतिरिक्त हमें राष्ट्रीय विकास के लिए नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा।

संदर्भः-

1. मुखर्जी, राधा कुमुद (1951)-ऐन्षियेन्ट इण्डियन एजुकेशन, दिल्ली, मोतीलाल बनारसी दास।
2. योजना, जनवरी, 2016
3. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986
4. गुप्ता, एस.पी. तथा अलका गुप्ता (2007)-भारतीय शिक्षा का तानाबाना, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन
5. Diwakar, R.R (2009) - Bihar Through the Ages, Orient Longmans
6. https://hi-vikaspedia.in/e-governance